RNI : UAHIN/25/A3210

आवाम इंडिया

हिन्दी साप्ताहिक

छात्र-छात्राओं को मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
धन सिंह रावत -पेज 3

वर्षः 01 अंकः 12 देहरादून, शुक्रवार 03 जुलाई 2026 मूल्य 2 रुपये पृष्ठः 8 www.aawamindia.com

आपदा प्रबंधन केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आईटी पार्क, देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय मानसून पूर्व मॉक ड्रिल में अधिकारियों को प्रभावी आपदा प्रबंधन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे संवेदनशील राज्य में आपदा प्रबंधन केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूर्व तैयारी, त्वरित निर्णय, बेहतर समन्वय तथा आधुनिक तकनीकों का समुचित उपयोग अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन तंत्र की क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन को केवल राहत एवं बचाव तक सीमित न रखकर जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी तथा तकनीक आधारित प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एआई आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग तथा डेटा आधारित जोखिम आकलन जैसी आधुनिक तकनीकों को आपदा प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है, जिससे संभावित खतरों का समय रहते सटीक आकलन कर जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके।

उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित राहत एवं बचाव सुनिश्चित करने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीमों को सशक्त बनाया गया है तथा अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों तक समय पर चेतावनी पहुंचाई जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल स्रोत संरक्षण, ग्लेशियर अध्ययन, पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण तथा जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है ।उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण ही आपदा जोखिम को कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में संचालित विभिन्न राहत एवं बचाव अभियानों ने वैज्ञानिक सोच, आधुनिक तकनीकों, त्वरित निर्णय क्षमता तथा टीम वर्क की उत्कृष्ट मिसाल प्रस्तुत की है। उन्होंने निर्देश दिए कि मॉक ड्रिल के दौरान प्राप्त अनुभवों एवं कमियों का गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तथा सभी जनपद 72 घंटे के भीतर अपनी विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को आपदा सुरक्षा उपायों, आपातकालीन संपर्क नंबरों एवं प्राथमिक सावधानियों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आपदा के बाद राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि आपदा जोखिम को न्यूनतम करना, जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उत्तराखण्ड को देश का सबसे सक्षम, तकनीक-सक्षम एवं जनभागीदारी आधारित आपदा प्रबंधन मॉडल बनाना है। उन्होंने सभी से पूर्व तैयारी, आधुनिक तकनीक, प्रभावी समन्वय एवं जनभागीदारी के बल पर उत्तराखण्ड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन योजना तथा राज्य के सभी 13 जनपदों की जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं का विमोचन भी किया।

उन्होंने इस अवसर पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एवं अग्निशमन विभाग द्वारा लगाए गए आधुनिक राहत एवं बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्हें उपकरणों के संचालन, उपयोगिता एवं आपदा के दौरान उनकी भूमिका की विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रदर्शनी में विशेष रूप से एनडीआरएफ द्वारा सीबीआरएनई (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु एवं विस्फोटक) आपदाओं में उपयोग किए जाने वाले अत्याधुनिक उपकरण आकर्षण का केंद्र रहे।

इसके अतिरिक्त डीप डाइविंग सेट, नाइट विजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलिक कटर, अंडरवाटर कम्युनिकेशन सिस्टम, अंडरवाटर ड्रोन तथा सोनार सिस्टम सहित अनेक आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला, लेफ्टिनेंट कर्नल (से. नि)रघुवीर सिंह भण्डारी, सचिव विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप, आईजी अग्निशमन श्रीमती विम्मी सचदेव, अपर सचिव प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शिक्षकों के स्थानांतरण को मिलेगा अतिरिक्त समयः डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण के लिये अतिरिक्त समय मांगने के साथ ही स्थानांतरण एक्ट से छूट देने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा जायेगा, ताकि प्रदेश के जिन विद्यालयों में पर्याप्त छात्र संख्या के बावजूद शिक्षकों के पद रिक्त हैं उनको भरा जा सके। इसके अलावा शिक्षकों के पदोन्नति प्रकरण के स्थाई समाधान को अंतिम विकल्प के रूप में अध्यादेश लाने पर भी विचार गया जा सकता है। इस संबंध में शासन स्तर पर न्याय, कार्मिक एवं वित्त विभाग के साथ सहमति बना ली गई है।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें मुख्य सचिव सहित, न्याय, कार्मिक व वित्त विभाग के उच्चाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण एवं पदोन्नति के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण को विचार-विमर्श किया गया। डा. रावत ने बताया कि शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण एवं वरिष्ठता का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते विभागीय स्तर पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सका है। उक्त के दृष्टिगत उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण को लेकर स्थानांतरण एक्ट में छूट के साथ ही समयवृद्धि की मांग का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजे जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त शिक्षकों के पदों को धारा-27 एवं अनुरोध श्रेणियों के आधार पर भरा जा सके। इसके लिये महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को शीघ्र दोनों प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है। डॉ. रावत ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के वरिष्ठता प्रकरण भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके चलते विभाग पदोन्नति देने में असमर्थ है, जबकि शिक्षक संगठन लगातार पदोन्नति की मांग को लेकर मुखर है। जिसको देखते हुये शासन ने कोर्ट के निर्णय में समय लगने की सम्भावना के मध्यनजर अंतिम विकल्प के रूप में पदोन्नति हेतु अध्यादेश लाने का विकल्प खुला रखा है।

(शेष पृष्ठ दो पर)

पीएम गतिशक्ति उपयोग मामलों का संग्रह 2.0 का विमोचन

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आज सचिवालय में नियोजन विभाग द्वारा आयोजित पीएम गतिशक्ति उपयोग मामलों का संग्रह 2.0 का विमोचन एवं विभागीय डेटा संग्रहण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के शुभारंभ समारोह सहित दो दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से पृथ्वी पर किसी भी स्थान से संबंधित जानकारी को एकत्र, विश्लेषित, प्रदर्शित और उपयोग किया जाता है।

मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल और जियोस्पेशियल तकनीक को महत्त्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से सड़क, विद्युत लाइन, पानी की लाइन, रेलवे लाइन, भवन निर्माण, डैम और अन्य बड़े निर्माणों में जियोस्पेशियल तकनीक एक बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि इससे किसी भी प्रोजेक्ट की जियो लोकेशन और अन्य विभागों से समन्वय में बहुत सहायता मिलेगी। इसमें दूसरा सबसे बड़ा फायदा विभागों के मध्य डेटा इंटीग्रेशन से होगा।

सभी विभाग अपने स्तर से जितनी अधिक प्रामाणिक जानकारियां इस पोर्टल में अपलोड करेंगे, योजनाओं के निर्माण में उतने बेहतर परिणाम आएंगे, जिससे इस प्लेटफार्म का और अच्छे से उपयोग किया जा सकेगा और अन्य विभागों से अच्छे से सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा।

मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को व्यय वित्त समिति की बैठकों में इस प्लेटफार्म का उपयोग किए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इससे योजना का एक बेहतर आंकलन किया जा सकेगा। उन्होंने 10 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट में साईट सिलेक्शन कमेटी को पीएम गतिशक्ति पोर्टल की जियोस्पेशियल तकनीक से मैपिंग अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी नई स्वीकृत योजनाओं को भी इस पोर्टल पर अपलोड किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं में डुप्लीकेसी नहीं हो सकेगी और विभिन्न विभागों के मध्य तालमेल में आसानी होगी।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को मास्टर रिसोर्स पर्सन चिन्हित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय एजेन्सी Bhaskaracharya Institute for Space Applications and Geoinformatics (BISAG-N) द्वारा तैयार इस एप्लीकेशन को स्टेट प्रगति पोर्टल (उन्नति) से एकीकृत किए जाने की बात कही। साथ ही इससे सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता के लिए विभागों को लगातार कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के साथ ही BISAG-N के पास जाकर प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव एल. फैन्नई, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. एस.एन. पाण्डेय, श्रीधर बाबू अद्धांकी, अपर सचिव हिमांशु खुराना, नरेन्द्र सिंह भण्डारी, बंशीधर तिवारी एवं BISAG-N सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शिक्षकों के स्थानांतरण को मिलेगा अतिरिक्त.....

पृष्ठ 1 का शेष......

इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को अध्यादेश का प्रस्ताव भी तैयार रखने को कहा गया है, ताकि उच्च न्यायालय में दायर वादों का समय पर निराकरण न होने के दृष्टिगत अध्यादेश लाकर वरष्ठिता का निर्धारण करते हुये शिक्षकों पदोन्नति दी जा सके।

बैठक में शिक्षकों के त्रिस्तरीय ढांचे सहित एससीईआरटी व डायट के नये ढांचे के गठन एवं नियमावली बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये गये। इसके अतिरिक्त विभागीय मंत्री ने कहा कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के शत-प्रतिशत प्रस्ताव तीन दिन के भीतर मंगा लिये जाय, ताकि धनराशि आवंटित की जा सके। उन्होंने प्रदेशभर के सभी विद्यालयों में शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण सुनिश्चित करने के साथ-साथ पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये। इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण तथा शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को नियमानुसार जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय अमित कुमार, सचिव कार्मिक शैलेष बगोली, सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा नमामि बंसल, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा आकांक्षा कोण्डे, अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद, संयुक्त निदेशक संस्कृत शिक्षा मंजू भारती सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

आउट ऑफ टर्न नौकरी पाने वाले अधिकांश खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्ति मिलः सीएम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा में समायोजित करने की प्रक्रिया को तय समय के अंदर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ टर्न नौकरी पाने वाले अधिकांश खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्ति मिले, इस पर भी कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप ही राज्य में नई खेल नीति लाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय-गोलापार, हल्द्वानी में आगामी माह से सत्र को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोला पार स्टेडियम में प्रवेश प्रक्रिया एवं कोच, कर्मचारी, अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत मिनी स्टेडियमों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लेगेसी प्लान पर तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा महाराणा प्रताप स्पोटर्स कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी गोला पार स्टेडियम, रुद्रपुर वेलोड्रोम, टिहरी झील, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ स्थित स्टेडियमों में विकसित की गई सुविधाओं को खिलाड़ियों के लिए और उपयोगी बनाई जाए। उन्होंने कहा 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के दौरान विकसित किए गए बुनियादी ढांचे के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 के संबंध में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न विधाओं में विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन शुरू किया जाए। विभिन्न खेल संघों के साथ खिलाड़ियों की चयन/चिन्हीकरण प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा राज्य सरकार का संकल्प आगामी राष्ट्रीय खेलों में और बेहतर प्रदर्शन कर देवभूमि को खेलभूमि के रूप में भी स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक स्पोटर्स के तहत सभी जनपदों में निर्धारित खेलों के लिए कोचिंग, प्रतिभा पहचान एवं प्रतिस्पर्धा को भी विकसित किया जाए। प्रत्येक जिला खेल छात्रावास को उस जनपद के निर्धारित खेल हेतु व्कै खेल नर्सरी के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में बताया गया कि अब तक कुल 29 मेडल धारक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा चुका है। इसके साथ एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत अब तक कुल 48 मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है।

कैबिनेट मंत्री ने ली भिलाडू स्टेडियम के संबध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को अपने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भिलाडू में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण को लेकर खेल विभाग, वन विभाग एवं पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्टेडियम निर्माण से जुड़ी भूमि हस्तांतरण एवं एक्सेस मार्ग (पहुंच मार्ग) की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्टेडियम निर्माण से संबंधित भूमि हस्तांतरण, पहुंच मार्ग और अन्य तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि परियोजना में किसी प्रकार की देरी न हो और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके। बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि वन विभाग की आपत्तियों से संबंधित फाइल शासन को प्रेषित कर दी गई है तथा शीघ्र ही आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि भिलाडू स्टेडियम के निर्माण हेतु विस्तृत प्राक्कलन (इस्टीमेट) एक सप्ताह के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राक्कलन तैयार होते ही शासन स्तर से सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भिलाडू में स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इससे खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता निखारने का अवसर मिलेगा, खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को उचित मंच प्राप्त होगा। साथ ही, क्षेत्र में खेल गतिविधियों के विस्तार के साथ स्थानीय विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।बैठक में डीएफओ मसूरी अमित कुंवर, परियोजना प्रबंधक पेयजल निगम रविंद्र कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा) संजय सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी शुभांगी गुरुंग आदि उपस्थित रहे।

बीडीसी बैठक में जनप्रतिनिधियों ने उठाए विकास के मुद्दे

रूद्रप्रयाग । विकासखंड जखोली के ब्लॉक सभागार में आज ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विनीता चमोली की अध्यक्षता में बीडीसी बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या

में प्रतिभाग कर अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े विकासात्मक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने सड़क, पेयजल, सिंचाई, आवास, विद्युत एवं ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे और संबंधित विभागों से समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विनीता चमोली ने कहा कि बीडीसी बैठक जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां स्थानीय समस्याओं को सीधे अधिकारियों के समक्ष रखा जाता है और उनके समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाती है।

बैठक में ग्राम प्रधान टाट ने बाल विकास विभाग से संबंधित मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र की मरम्मत कराने के साथ-साथ सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग रखी। उनका कहना था कि सुरक्षा दीवार बनने से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और ग्रामीणों को भी बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

वहीं ग्राम प्रधान बांसी ने अपने गांव स्थित शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मंदिर क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाने एवं आवश्यक सुविधाएं विकसित करने से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों की आस्था से जुड़े इस केंद्र को नया स्वरूप मिल सकेगा।

ज्येष्ठ प्रमुख नवीन सेमवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत सर्वेक्षण की तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि कई पात्र ग्रामीण अब तक सर्वेक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं। यदि सर्वेक्षण अवधि बढ़ाई जाती है तो अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

इसके अलावा प्रधान ग्राम पंचायत चौरा ने अपनी ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थलों पर सोलर लाइट लगाए जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि गांव के कई सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को रात के समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सोलर लाइट लगने से न केवल रोशनी की समस्या दूर होगी बल्कि ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

ग्राम प्रधान मुन्नादेवल पुनीत डिमरी ने क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को लेकर नहरों की मरम्मत की मांग रखी। उन्होंने बताया कि कई नहरें क्षतिग्रस्त होने के कारण किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही है। नहरों की मरम्मत होने से कृषि कार्य सुचारु रूप से संचालित होंगे और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आवश्यक जानकारी साझा की तथा समस्याओं के समाधान हेतु सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि विकास कार्यों को गति देने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विभाग पूरी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं।

बैठक के अंत में ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विनता चमोली ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच सतत संवाद एवं सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बैठक में उठाए गए सभी प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों तक पहुंचाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती रितु नेगी, ज्येष्ठ प्रमुख नवीन सेमवाल, कनिष्ठ प्रमुख राजेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, जिला विकास अधिकारी अनिता पंवार,उप जिलाधिकारी भगत सिंह फोनिया, खंड विकास अधिकारी विजय सिंह नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

छात्र-छात्राओं को मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा-धन सिंह रावत

देहरादून । सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नव सृजित तीनों कैम्पस के लिये शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग में 244 नये पद सृजित कर दिये गये हैं।

जिसका शासन स्तर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। इन पदों के सृजन से तीनों परिसरों को पहली बार अपना स्थायी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ढांचा मिल गया है। जिससे शिक्षण, शोध एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को नई गति मिलेगी और छात्र-छात्राओं को सीधे तौर पर इसका लाभ प्राप्त होगा।

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नव सृजित तीन कैम्पस बागेश्वर, चम्पावत तथा पिथौरागढ़ में शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग के तहत 244 नये पद सृजित कर दिये हैं। जिसमें शैक्षणिक संवर्ग के तहत बागेश्वर परिसर में यूजीसी मानकों के तहत विभिन्न विषयों में 38 पद सृजित किये गये हैं। जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 29, एसोसिएट प्रोफेसर 8 तथा प्रोफेसर का 01 पद शामिल है। इसी प्रकार चम्पावत परिसर के लिये 31 पद सृजित किये गये हैं। जिसमें 30 पद असिस्टेंट प्रोफसर व एक पद एसोसिएट प्रोफेसर का है। जबकि पिथौरागढ़ परिसर में 95 पद सृजित किये गये हैं। जिसमें अस्टिेंट प्रोफेसर 59, एसोसिएट प्रोफेसर 20 तथा प्रोफेसर के 16 पद शामिल है। इसके अतिरिक्त तीनों कैम्पस के लिये शिक्षणेत्तर पदों का भी सृजन किया गया। प्रथम चरण में बागेश्वर परिसर में 22, चम्पावत 17 तथा पिथौरागढ़ परिसर के लिये 41 पद सृजित किये गये। जिनमें पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयध्यक्ष, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखाकार, प्रधान सहायक, वैयक्तिक सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, पर्यावरण मित्र, माली परिचर व अनुसेवक आदि के पद शामिल हैं। शासन स्तर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जिसके तहत पूर्व में तीनों महाविद्यालयों के लिये सृजित शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर संवर्ग के कुल 329 पदों को उच्च शिक्षा विभाग को समर्पित कर दिये गये हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिन पदों पर आउटसोर्स व्यवस्था लागू होगी, उन पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप अधिकृत एजेंसी के माध्यम से शीघ्र कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। स्थायी पदों के सृजन से तीनों परिसरों में शिक्षण कार्य, शोध गतिविधियों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा।

डॉ. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड ने कहा की सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के तीनों कैम्पस बागेश्वर, चम्पावत व पिथौरागढ़ के लिये शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर संवर्ग में 244 पदों का सृजन कर दिया गया है। इन पदो के सापेक्ष तीनों परिसरों में शिक्षकों व कार्मिकों का समायोजन किया जायेगा, जबकि आउटसोर्स के पदों को भी आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से शीघ्र भरा जायेगा। नये पदों के सृजन से विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियां अधिक प्रभावी, व्यवस्थित एवं सुचारु रूप से संचालित हो सकेंगी।

मुख्य सचिव ने 40 गतिमान परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी

देहरादून । मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी 40 गतिमान परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने सभी सम्बन्धित सचिवगणों को निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट्स की नियमित समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को प्रोजेक्ट्स निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होने की उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट अपडेट करते समय प्रोजेक्ट के पूर्ण होने की तिथि का भी उल्लेख किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत में पूर्ण होने वाले कार्यों को मानसून सीजन के दृष्टिगत लगातार मॉनिटरिंग करते हुए कार्यों को पूर्ण कराया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत महासू देवता हनोल में समग्र बुनियादी ढांचे का निर्माण एवं जागेश्वर धाम मंदिर से सम्बन्धित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए प्रतिदिन समीक्षा करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराया जाए। उन्होंने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित देहरादून में जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी प्रणाली का विकास कार्य को भी शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु नियमित मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग को लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना (300 मेगावाट), 220 केवी बनबसा सबस्टेशन (100 एमवीए) और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइन; चमोली में 400 केवी पिपलकोटी स्विचिंग सबस्टेशन और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइन सहित टिहरी जिले के घनसाली में 220 केवी घनसाली सबस्टेशन के निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टाईमलाइन के अनुरूप फॉरेस्ट क्लीयरेंस और भूमि हस्तांतरण आदि से सम्बन्धित मामलों की लगातार पैरवी करते हुए कार्यों की निगरानी की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन परियोजनाओं का कार्य लगभग पूर्ण होने की कगार पर है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को विभाग प्राथमिकता पर लेते हुए शीघ्र पूर्ण कराएं। उन्होंने 13 जनपदों के लिए 73 पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 133 सड़कों (96 प्रतिशत पूर्ण) और 151 पुलों के निर्माण कार्य (97 प्रतिशत पूर्ण) सहित नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत उधमसिंहनगर में नदी पुनर्जीवन कार्य (98 प्रतिशत) जैसे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनाई, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव शैलेश बगौली, सहित सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

सम्पादकीय

उत्तराखंड में मानसूनः तैयारियां, चुनौतियां और उपाय

उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। अमूमन बारिशें गर्मी से राहत लेकर आती हैं लेकिन यहीं बारिशें पहाड़ में चुनौतियां और प्राकृतिक शक्ति का अहसास कराती हैं। कब जीवनदायिनी वर्षा आपदा का रूप धारण कर ले पता नहीं चलता है। यहां भौगोलिक परिस्थितियाँ ही ऐसी है कि कई बार भारी वर्षा जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर देती है। भूस्खलन, बादल फटना, नदी में अचानक जलस्तर बढ़ना, सड़कें बंद होना और बिजली-पानी जैसी मूलभूत सेवाओं का प्रभावित होना आम बात हो जाती है। हालांकि सरकार और प्रशासन चुनौतियों से निपटने के लिए अपने स्तर पर तैयारी करता है और कार्य करता है लेकिन आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अधिक जागरूक, सावधान और सहभागी बने।

उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में हमें मानसून के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। यदि यात्रा करनी ही पड़े तो मौसम की जानकारी अवश्य लें और संवेदनशील पहाड़ी मार्गों पर रात में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि हमारे क्षेत्र में बारिश लम्बे समय से हो रही है तो हमें सरकार की गाइडलाइन को अवश्य मानना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों के पास प्रशासन के आपातकालीन नम्बर होने चाहिए। यदि आप दुर्गम क्षेत्र में हो तो अपना मोबाइल हमेशा चार्ज रखें और पावर बैंक साथ रखें। प्रत्येक घर में में टॉर्च, पीने का पानी, सूखा भोजन, प्राथमिक उपचार किट, आवश्यक दवाइयाँ और महत्वपूर्ण दस्तावेज वाटरप्रुफ बैग में सुरक्षित होने चाहिए। ये प्राथमिक और जरूरी उपाय है जो हम सभी नागरिकों को बिना किसी डर के अपनाने चाहिए।

दूसरा पहाड़ में यात्रा के दौरान ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। कभी भी भूस्खलन क्षेत्र या सड़क पर बह रहे बरसाती गदेरों को पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि सड़क पर अचानक पत्थर गिरने लगें या पहाड़ से मिट्टी खिसकने लगे तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ। इस दौरान हमेशा प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए और अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ईश्वर ना करें यदि कोई अनहोनी हो जाये तो बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। खासकर जो श्रद्धालु उत्तराखंड में आते हैं। वो पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति से अंजान होते हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

तीसरा मानसून के दौरान नदी और नालों से दूरी बनाकर रखें। लगातार बारिश से ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अचानक बादल फटने की घटनाएँ सामने आती हैं जिससे नदियों में अचानक तेज बहाव आता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में नदियों के करीब जाना या नहाने का प्रयास करना खतरनाक साबित हो सकता है।

हालांकि उत्तराखंड में दीर्घकालिक आपदा प्रबंधन नीति पर लम्बे समय से काम किया जा रहा है। पर प्रकृति अपने होने का और अपनी शक्ति का बीच-बीच में अहसास करा देती है। इन प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही तैयारी, सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से इसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपदा के दौरान रिस्पांस टाइम बहुत मायने रखता है। जितनी जल्दी हम राहत कार्य शुरू करते हैं वो समय ही इस आपदा के जोखिम को कम करता है। शायद यहीं हमें काम करने की आवश्यकता है। संवेदनशील क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए जो मानसून से पहले भी और मानसून समाप्त होने के बाद भी होना चाहिए। साथ ही आधुनिक चेतावनी प्रणाली, प्रशिक्षित राहत दल और पर्यावरण संरक्षण पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। हम कई बार बड़ी चुनौतियों से निपटे हैं। बहुत कुछ खोया है मगर हिम्मत के साथ उभरना जानते हैं। ईश्वर ना करें कि फिर कोई चुनौती सामने आये लेकिन सावधानी और जागरूकता बहुत जरूरी है। एक बेहतर आज के लिए और बेहतर कल के लिए भी।

एक बार फिर आपके द्वार पहुंच रही है धामी सरकार

देहरादून। जन समस्याओं के निराकरण के लिए गत वर्ष चलाए गए 'जन जन की सरकार-जन जन के द्वार' कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए, प्रदेश सरकार एक बार फिर जनता के द्वार पहुंच रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई से 15 दिन का इस विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इसमें जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संबंधित विभागों अधिकारी- कर्मचारी शामिल होकर, जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लोगों को जन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, बल्कि विभाग अधिकारी कर्मचारी खुद लोगों के पास पहुंच शिकायतों का निस्तारण करें। मुख्यमंत्री की इसी सोच को केंद्र में रखते हुए प्रदेश सरकार ने गत दिसंबर माह से 45 दिन का 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान शुरु किया था। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के सफल पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक बार फिर ये अभियान शुरु होने जा रहा है। इस बार 4 जुलाई से मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा (15 दिवस) के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसके तहत जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर शिविर आयोजित करते हुए, जन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, साथ ही लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा।

पिछली बार 5 लाख से अधिक की थी जनभागीदारीदिसंबर माह में शुरु किए गए 45 दिन के 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के तहत 681 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 5,33,452 नागरिकों ने प्रत्यक्ष तौर पर भागीदारी निभाई, यही नहीं इस दौरान करीब 33 हजार जन शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया। इस अभियान को गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिस के रूप भी सराहा गया।लोगों को बिना किसी भागदौड़ के सरकारी सेवाएं मिली, यही सुशासन की पहली सीढ़ी है। इसी क्रम में सभी जनपदों में 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान का दूसरा चरण शुरु किया जा रहा है।

सिल्क्यारा सुरंग अब "बाबा बौखनाग महाराज सुरंग" के नाम से जानी जाएगी, बैठक में बनी सहमति

बड़कोट /उत्तरकाशी। उत्तराखंड की बहु चर्चित सिल्क्यारा सुरंग का नाम अब क्षेत्र के आराध्य देवता श्री बौखनाग महाराज के नाम पर रखा जायेगा!सोमवार को तहसील बड़कोट में आयोजित बैठक में सर्व सहमति से एक प्रस्ताव तैयार कर उपजिलाधिकारी बड़कोट के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया है!

चारधाम आल वेदर रोड परियोजना के तहत धरासु - ब्रह्मखाल -फूलचट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन पोलगांव-सिलक्यारा सुरंग का नाम अब श्बाबा बौखनाग महाराज सुरंगश रखने पर सर्वसम्मति बन गई है। सोमवार को बड़कोट में उपजिलाधिकारी बृजेश कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों, बाबा बौखनाग देवता समिति, यमुनोत्री होटल एसोसिएशन तथा स्थानीय ग्रामीणों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

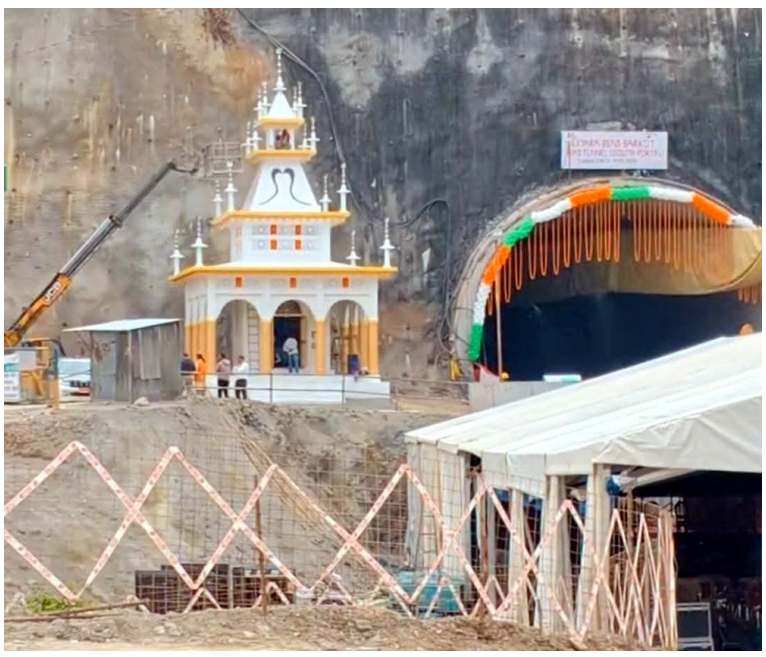

बाबा बौखनाग देवता समिति एवं यमुनोत्री होटल एसोसिएशन की ओर से सुरंग का नाम श्बाबा बौखनाग महाराज सुरंगश रखने संबंधी सहमति पत्र उपजिलाधिकारी को सौंपा गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर कर प्रस्ताव के प्रति अपनी सहमति दर्ज कराई। समिति ने मांग की कि सुरंग के दोनों छोर सिलक्यारा और पोलगांव पर बाबा बौखनाग महाराज के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया जाए। इसके साथ ही बाबा बौखनाग की आस्था से जुड़े बौख टिब्बे को धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी मांग रखी गई। एसडीएम बृजेश कुमार तिवारी ने समिति को आश्वस्त किया कि सहमति पत्र और मांगपत्र शासन को भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी!बैठक में स्थानीय लोगों ने सुरंग के पोल गांव वाले साइड पर भी बौखनाग महाराज का भव्य मंदिर निर्माण कर आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यकरण करने की मांग शासन से की!

खाला गांव में बरसात से क्षतिग्रस्त मार्ग का कैबिनेट मंत्री ने किया निरीक्षण

देहरादून । कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को देहरादून के खालागांव पहुंचकर भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए गांव को जोड़ने वाले मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से क्षति की जानकारी लेते हुए पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी देहरादून आशीष चौहान को क्षतिग्रस्त सड़क एवं सुरक्षा दीवार के पुनर्निर्माण का शीघ्र इस्टीमेट तैयार कर तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए प्रभावित मार्ग को जल्द से जल्द सुचारु करना आवश्यक है, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी पुश्ता निर्माण के कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए खालागांव के नाले में चेक डैम निर्माण का इस्टीमेट तैयार करने को भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चेक डैम बनने से भविष्य में बरसाती पानी के तेज बहाव से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा तथा ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 30 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी और शीघ्रता के साथ गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य पूरा कराया जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून आशीष चौहान, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार, सुंदर सिंह सहित जिला प्रशासन के अधिकारी एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

चिकित्सकों के सम्मान में समारोह आयोजित

देहरादून। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन द्वारा ओमकार सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, किशन नगर चौक कोलागढ़ रोड देहरादून में चिकित्सकों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री एवं वरिष्ठ अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉ. बी.के.एस. संजय रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष सचिन जैन ने की। इस अवसर पर पद्मश्री डॉ. बी.के. एस. संजय (अध्यक्ष, एम्स गुवाहाटी), डॉ. विशाल गुप्ता (अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ), डॉ. नेहा अग्रवाल (वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट), डॉ. ओ.पी. गुप्ता (नेत्र रोग विशेषज्ञ) तथा डॉ. पवन कुमार गोयल (होम्योपैथिक चिकित्सक) को उनकी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। डॉ. नेहा अग्रवाल वर्तमान में ग्राफिक एरा हॉस्पिटल, देहरादून में वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वहीं डॉ. विशाल गुप्ता एवं डॉ. नेहा अग्रवाल दोनों ओमकार सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, कोलागढ़ रोड तथा ग्राफिक एरा हॉस्पिटल के माध्यम से भी मरीजों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

मुख्य अतिथि डॉ. बी.के.एस. संजय एवं अन्य वक्ताओं ने अपने संबोधन में सभी चिकित्सकों को समाज के प्रति उनकी समर्पित एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि चिकित्सक मानवता की सेवा का सर्वोच्च उदाहरण हैं और उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा।

कार्यक्रम का संचालन संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मधु जैन ने किया। समारोह के अंत में सभी सम्मानित चिकित्सकों ने संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के सम्मान समारोह उन्हें और अधिक समर्पण एवं उत्साह के साथ समाज की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर सुनील अग्रवाल, नरेश चंद जैन, अरुण चावला, सुरेंद्र पाल सिंह, सोनिया रावत, प्रदीप नगलिया सहित संगठन के पदाधिकारी एवं अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के डीएम ने दिए निर्देश

देहरादून । जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने 23 जून 2026 को सहारनपुर रोड स्थित लाल पुल के निकट हुई बस दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु तथा चार

अन्य के घायल होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए, जिलाधिकारी द्वारा, उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 23 जून 2026 को लगभग प्रातः 11 बजे वाहन संख्या यूके07पीए-0287 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में राजीवनगर, पटेलनगर निवासी आहद (22 वर्ष) की मृत्यु हो गई, जबकि चार अन्य व्यक्ति घायल हुए। संबंधित वाहन नगर बस सार्वजनिक सेवायान की श्रेणी में संचालित है।

जिलाधिकारी ने जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन एवं निष्पक्ष जांच करते हुए एक सप्ताह के भीतर अपनी आख्या प्रस्तुत करें। जांच के दौरान दुर्घटना के कारणों, वाहन में चालक सहित सवार यात्रियों की संख्या, मृतक एवं घायलों का वास्तविक विवरण, घायलों की चिकित्सकीय स्थिति, मृतक के उत्तराधिकारियों का विवरण, परिवहन विभाग की तकनीकी रिपोर्ट, वाहन के कर एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुझावों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। उक्त के घटना के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को लिखित एवं मौखिक रूप में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं अथवा कोई जानकारी देनी है वह एक सप्ताह के भीतर उप जिलाधिकारी सदर के कार्यालय एवं न्यायालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित प्रस्तुत कर सकते हैं।

बिगड़ती कानून व्यवस्था को सही करने की मांग

देहरादून। उत्तराखंड आन्दोलनकारी संयुक्त परिषद एवं विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक संगठनों की ओर से हम आपके समक्ष अत्यंत गंभीरता एवं चिंता के साथ निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य में पिछले कुछ समय से कानून-व्यवस्था की स्थिति जिस प्रकार दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, उसने आम जनमानस में भय एवं असुरक्षा का वातावरण पैदा कर दिया है।

हम आपका ध्यान निम्नलिखित गंभीर मुद्दों की ओर दिलाना चाहते हैं :

1. हाल के दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में हथियारों से लैंस तीर्थयात्रियों द्वारा स्थानीय लोगों को जगह-जगह धमकाने, आतंकित करने एवं शांति व्यवस्था भंग करने की घटनाएँ सामने आई हैं। इससे स्थानीय निवासियों में भय का संचार हुआ है तथा पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार को भी गंभीर क्षति पहुँची है।

2. राज्य में कुछ असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्व सक्रिय हैं,जो कई संवेदनशील घटनाओं जो अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले करने तथा उनके रोजगार को समाप्त करने के पढयन्त्र में लिप्त हैं। ऐसी गतिविधियाँ उत्तराखण्ड की सामाजिक सद्भावना एवं एकता के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं।

3. अराजकता एवं असुरक्षा के कारण स्थानीय व्यापार, पर्यटन एवं छोटे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे पहाड़ी युवाओं के रोजगार के अवसर सिमटते जा रहे हैं।

अतः हमारी आपसे विनम्र माँगें इस प्रकार हैं :

(क) किसी भी तीर्थयात्री को ख़ चाहे वह किसी भी धर्म विशेष का हो ख़ हथियार ले जाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए यात्रा मार्गों पर चेकिंग बढ़ाई जाए तथा सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया जाए।

(ख) असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों पर कड़ा अंकुश लगाया जाए। ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए तथा उनके विरुद्ध त्वरित एवं सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए समयबद्ध व्यवस्थाओं के निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार के पांच वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के अवसर पर प्रदेशभर में सात दिवसीय

विशेष वृहद जन कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। श्जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वारश् के संकल्प के साथ शुरू हो रहे इस अभियान के तहत आगामी 4 जुलाई को ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में एक विशाल बहुउद्देशीय और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। इस मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं शिरकत करेंगे।

ऋषिकेश में आयोजित होने वाले इस महाशिविर की तैयारियों का जायजा लेने मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल जिले के आला अधिकारियों के साथ आईडीपीएल मैदान पहुंचे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ऋषिकेश भौगोलिक रूप से एक 'स्ट्रैटेजिक लोकेशन' (सामरिक स्थान) है। इसे देखते हुए इस शिविर में देहरादून के साथ-साथ पड़ोसी जनपद टिहरी और हरिद्वार से भी बड़ी संख्या में आम जनता और लाभार्थियों के पहुंचने की उम्मीद है। जनता की सुविधा के लिए तीनों जिलों के विभागीय अधिकारी एक साथ मौजूद रहेंगे और एक 'इंटीग्रेटेड एफर्ट' (एकीकृत प्रयास) के तहत मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य 'त्वरित लाभ और त्वरित समाधान' होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान एक विशाल चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, जहां क्रोनिक (गंभीर व पुरानी) बीमारियों की जांच से लेकर सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के कार्ड मौके पर ही बनाए जाएंगे। बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न विभागों की स्टॉल लगेंगी, जिससे आम जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। महाशिविर में उमड़ने वाली भारी भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने सुरक्षा, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। प्रदेश में 'सेवा, सुशासन एवं समर्पण' अभियान के तहत आगामी 4 जुलाई से शुरू होने वाले 'सेवा सप्ताह' के भव्य आयोजन के लिए उत्तराखंड सूचना विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। तैयारियों को समय से अंतिम रूप देने के लिए सूचना विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल मैदान का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य मंच निर्माण, आम जनता के सुगम आवागमन, पार्किंग और बैठक व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम में आने वाले आम जनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी पुख्ता इंतजाम समय रहते दुरुस्त कर लिए जाएं। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंन्द्र डोबाल, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह सहित रेखीय विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड कांग्रेस विचार विभाग की वैचारिक बैठक आयोजित

देहरादून। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टेन प्रवीण डागर ने कहा कि वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में कांग्रेस के मूल

विचार-समता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, भारतीय राष्ट्रवाद तथा संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विचार विभाग की भूमिका केवल संगठन के भीतर वैचारिक विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में लोकतांत्रिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवैधानिक मूल्यों तथा तथ्याधारित सार्वजनिक संवाद को सशक्त करना भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने देशभर में विचार विभाग को अधिक सक्रिय, शोध-आधारित तथा समाज के विभिन्न वर्गों से सतत संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। वे आज राजीव भवन, देहरादून में उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस विचार विभाग (बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ) द्वारा आयोजित ष्विचार से परिवर्तन ख़ संविधान से राष्ट्र निर्माणष विषयक वैचारिक बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय तथा उत्तराखण्ड की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में कांग्रेस की वैचारिक भूमिका और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप जोशी ने कहा कि उत्तराखण्ड आज बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय संकट तथा पर्वतीय अर्थव्यवस्था जैसी अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विचार विभाग का उद्देश्य केवल राजनीतिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि समाज के समक्ष तथ्यपरक, संवेदनशील और समाधान-आधारित वैचारिक दृष्टि प्रस्तुत करना है। उन्होंने उत्तराखण्ड की परिस्थितियों के अनुरूप अध्ययन, जनसंवाद और नीति-आधारित विमर्श को विचार विभाग की प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में स्वागत उद्बोधन एवं बैठक का एजेंडा प्रस्तुत करते हुए डॉ. प्रेम बहुखण्डी ने कहा कि देश आज केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि वैचारिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समावेशी विकास जैसे मूल्यों पर आधारित सार्थक जनसंवाद समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि बैठक में उत्तराखण्ड में कांग्रेस की वैचारिक भूमिका को सशक्त बनाने, पर एक व्यापक वैचारिक दस्तावेज तैयार करने जैसे विषयों पर विचार किया गया।

उप जिला चिकित्सालय को मेडिकल उपकरण समर्पित

मसूरी। सोमवार को ओएनजीसी द्वारा वित्त पोषित एवं सरस्वती जनकल्याण व स्वरोजगार संस्थान, देहरादून के सहयोग से सिविल अस्पताल मेडिकल उपकरण

वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी रहे।

इस अवसर पर मंत्री जोशी ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया तथा अस्पताल को विभिन्न आधुनिक चिकित्सा उपकरण समर्पित किए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ओएनजीसी के सहयोग से उपलब्ध कराए गए ये उपकरण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाएंगे तथा स्थानीय लोगों के साथ-साथ मसूरी आने वाले पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान अस्पताल प्रशासन ने जानकारी दी कि सिविल अस्पताल, मसूरी में प्रतिदिन लगभग 400 मरीजों की ओपीडी संचालित होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह लगभग 35 से 40 सुरक्षित प्रसव कराए जाते हैं। अस्पताल में एक्स-रे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं भी नियमित रूप से उपलब्ध हैं, जिससे क्षेत्र की बड़ी आबादी को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने ओएनजीसी एवं सरस्वती जनकल्याण स्वरोजगार संस्थान के इस जनहितकारी प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सहयोग से सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावी एवं जनोपयोगी बनेंगी। कार्यक्रम में मण्डल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व मण्डल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, अरविन्द सेमवाल, विजय बिंदवाल, विजय बुटोला, अभिलाष, सचिन, महिला मोर्चा अध्यक्ष जसोदा शर्मा, अनिता धनाई, कमला थपलियाल, सपना शर्मा, सीता पँवार, गुड्डी देवी चिकित्सकगण, अस्पताल प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

आमिर खान ने तीसरी शादी की खबरों पर लगाई मुहर! 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट के साथ लेंगे सात फेरे, मुंबई वाले घर पर होगी सिंपल सेरेमनी

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान एक बार फिर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले काफी समय से चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए सुपरस्टार ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह 5 जुलाई, 2026 को अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अभिनेता अरशद वारसी की आगामी सीरीज प्रीतम और पेड्रो की स्क्रीनिंग के दौरान आमिर खान ने मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यह शादी बेहद सादगी भरी होगी, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग शामिल होंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हुए अपने फैंस का प्यार और दुआएं भी मांगीं। उम्मीद है कि आमिर खान और गौरी स्प्रैट 5 जुलाई को एक्टर के मुंबई वाले घर पर एक छोटी सी सेरेमनी में अपनी शादी रजिस्टर करेंगे, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य और करीबी दोस्त शामिल होंगे।

आमिर खान ने पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ 5 जुलाई को शादी कन्फर्म की

अपने बेटे जुनेद खान के साथ मीडिया से बात करते हुए आमिर खान ने कहा, ष्हां, मेरी शादी 5 जुलाई को हो रही है, और बहुत ही छोटी सी शादी है। घर पर ही कर रहे हैं, दोनों परिवारों के साथ। बहुत ही खास दिन है हमारे लिए। सबकी दुआएं और आशीर्वाद चाहेंगे। प्रार्थना करें कि हम खुश रहें और हमारा सफर अच्छा रहे।ष (हाँ, मेरी शादी 5 जुलाई को हो रही है, और यह बहुत छोटी शादी होगी। हम इसे घर पर दोनों परिवारों के साथ कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत खास दिन है। हम सभी की दुआओं और आशीर्वाद चाहते हैं। प्लीज दुआ करें कि हम खुश रहें और हमारा साथ का सफर अच्छा रहे।)

इंडिया टीवी को आमिर और गौरी की शादी के लिए प्लान किए गए मेन्यू के बारे में खास जानकारी मिली है। शादी का मेन्यू पूरी तरह से कपल के बच्चों ने प्लान किया है। सेलिब्रेशन से जुड़े एक सोर्स के मुताबिक, खाना ष्पूरी तरह से बच्चों ने ही बनाया और तय किया है,ष जो शादी के जश्न में भी एक्टिव रोल निभाएंगे।

इससे पहले, श्सितारे जमीन परश के एक्टर ने कहा था कि वह शादी को सिंपल रखना चाहते हैं। अपनी शादी के प्लान बताते हुए उन्होंने कहा, ष्यह घर पर एक बहुत ही सिंपल रजिस्टर्ड शादी होगी, जिसमें सिर्फ दोनों परिवार और बहुत करीबी दोस्त होंगे। हम दोनों इसे बहुत बेसिक रखना चाहते हैं।

जिन लोगों को नहीं पता, आमिर खान की पहले किरण राव से शादी हुई थी, जिनसे उनका एक बेटा आजाद राव खान है। उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता से उनके दो बच्चे जुनैद खान और इरा खान भी हैं। वहीं, गौरी का अपनी पिछली शादी से एक बेटा है। असल में बेंगलुरु की रहने वाली गौरी स्प्रैट का बैकग्राउंड फैशन और एंटरप्रेन्योरशिप में है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स लंदन से पढ़ाई की है और अभी आमिर खान प्रोडक्शंस के प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हुई हैं।

रिया चक्रवर्ती जन्मदिन: एमटीवी वीजे से जलेबी गर्ल तक का सफर, एक विवाद ने रिया चक्रवर्ती को पहुंचाया जेल

बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती आज यानी की 01 जुलाई को अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं। एक्ट्रेस अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं। साल 2012 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरूआत की थी। वहीं रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीरें साझा करती रहती हैं। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे

जन्म और परिवार

कर्नाटक के एक बंगाली परिवार में 01 जुलाई 1992 को रिया चक्रवर्ती का जन्म हुआ था। रिया चक्रवर्ती के पिता भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी रहे हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस से जुड़ा है।

टीवी करियर

रिया ने साल 2009 में एमटीवी के एक शो से अपनी करियर की शुरूआत की थी। वह सालों तक एमटीवी के साथ जुड़ी थीं। एमटीवी के लिए रिया चक्रवर्ती ने कई शोज होस्ट किए थे। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने साल 2012 में तेलुगु फिल्म तुनीगा तुनीगा से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था।

फिल्मी सफर

साल 2013 में आई फिल्म श्मेरे डैड की मारुतीश से रिया ने बॉलीवुड में एंट्री की थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा सकी। वहीं इसके बाद साल 2014 में रिया फिल्म सोनाली केबल में नजर आई थीं। इस फिल्म में रिया के अपोजिट अली फजल थे। लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास नहीं चली।

इसके बाद साल 2017 में एक्ट्रेस फिल्म बैंक चोर और साल 2018 में जलेबी फिल्म में नजर आई थीं। फिल्म श्जलेबीश भी सफल नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म के गाने काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। रिया चक्रवर्ती की अन्य फिल्मों की तुलना में इस फिल्म ने ठीक-ठाक बिजनेस किया था।

पर्सनल लाइफ

रिया की पर्सनल लाइफ की बात करें, तो उन्होंने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी थीं। बताया जाता है कि एक फ्रेंड की पार्टी में रिया और सुशांत की दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे थे। सुशांत की मृत्यु के बाद एक्ट्रेस विवादों में आ गई थीं। उन पर कई आरोप भी लगे थे और वह ड्रग्स केस में 27 दिनों के लिए जेल भी गई थीं। हालांकि उन पर लगे आरोप सही नहीं साबित हुए और वह बरी हो गईं।

चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पद से जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार सौंपा

नई दिल्ली। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीवीएसएम, एवीएसएम, चार दशकों से अधिक की विशिष्ट सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए और उन्होंने सेना प्रमुख

(सीओएएस) का पद त्याग दिया। उनके कार्यकाल को उच्च स्तर की परिचालन तत्परता बनाए रखने, सेवाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने, परिवर्तन की प्रक्रिया को गति देने और प्रौद्योगिकी आत्मसात करने, बल पुनर्गठन और सैनिक-केंद्रित पहलों को केंद्रित प्रोत्साहन देने के लिए याद किया जाएगा।

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सभी मोर्चों पर परिचालन तत्परता को उच्च प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में, भारतीय सेना ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत उत्तरी सीमाओं पर मजबूत और सतर्क रुख बनाए रखा और पश्चिमी मोर्चे पर दृढ़ संकल्प, संयम और व्यावसायिकता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। ऑपरेशन सिंदूर उनके कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो उभरते सुरक्षा परिवेश में सेना की तत्परता, सटीकता और सुनियोजित प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जनरल ऑफिसर ने भारतीय सेना के चल रहे परिवर्तन के दशक को सशक्त दिशा प्रदान की। उनके मार्गदर्शन में, भारतीय सेना ने बल पुनर्गठन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी आत्मसातकरण, संयुक्तता, प्रणाली सुधार और मानव संसाधन प्रबंधन में सुधार किए। रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्विनी ड्रोन प्लाटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ब्रिगेड और एकीकृत युद्ध समूह जैसी पहलों को एक आधुनिक, चुस्त और भविष्य के लिए तैयार बल के निर्माण के व्यापक प्रयास के अंतर्गत आगे बढ़ाया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया। उन्होंने भविष्य के संयुक्त, एकीकृत और युद्धक्षेत्र-उन्मुख अभियानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच अधिक एकीकरण, समान परिचालन सोच और बेहतर समन्वय को लगातार प्रोत्साहित किया। उनके कार्यकाल के दौरान सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों का कल्याण एक प्रमुख प्राथमिकता बनी रही। उन्होंने सेना का अपने सैनिकों और पूर्व सैनिकों से जुड़ाव मजबूत करने के उद्देश्य से कई पहलें शुरू कीं, जिनमें वेटरन्स अचीवर्स अवार्ड जैसी पहलों के माध्यम से उनके योगदान को सार्थक मान्यता देना शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सेना की अपने कर्मियों और उनके परिवारों के प्रति जिम्मेदारी सक्रिय सेवा से परे भी है। जनरल ऑफिसर ने विकसित भारत विजन /2047 और सशस्त्र बल विजन /2047 से प्रेरित होकर, भारतीय सेना की भविष्य की तैयारियों के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु सामरिक सुरक्षा दिशानिर्देश / 2047 के निर्माण का भी मार्गदर्शन किया। अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

पीएम मोदी का बड़ा लक्ष्य, 10 ट्रिलियन येन के निवेश से दोगुनी होंगी कंपनियां

दिल्ली में आयोजित भारत-जापान संयुक्त आर्थिक मंच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के चौथे वाहन निर्माण प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान के आर्थिक संबंध बेहद खास हैं और यह नया प्लांट हमारी इसी साझेदारी का एक चमकता हुआ उदाहरण है।

दुनिया की सुजुकी कारें भारत में बन रहीं

पीएम मोदी ने मंच को संबोधित करते हुए एक बड़ा आंकड़ा साझा किया। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में बिकने वाली सुजुकी की कुल कारों में से दो-तिहाई कारें अकेले भारत में बनाई जाती हैं, जिन्हें यहां से 100 से अधिक देशों में भेजा किया) जाता है। पीएम ने कहा, जब जापान की तकनीक और निवेश, भारत की रफ्तार और बड़े पैमाने के साथ मिलते हैं, तो इससे पूरी दुनिया को फायदा होता है। उन्होंने इस मंच से जुड़ने वाले नए जापानी व्यापारियों का भी स्वागत किया।

भारतीय अर्थव्यवस्था का बदल रहा है डीएनए

वैश्विक आर्थिक मंदी और व्यापारिक अनिश्चितता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब हालात मुश्किल होते हैं, तब मजबूत लोग ही आगे बढ़ते हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही है, जो इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाती है। पीएम ने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत ने जापान की काइजेन (लगातार सुधार करने की) सोच को अपनाया है, जिससे देश का आर्थिक डीएनए बदल रहा है।

व्यापार को और आसान बनाने के लिए पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही एक विशेष जापान बिजनेस वीक का आयोजन करेगा। इसमें पीएमओ के सीनियर अधिकारी जापानी बिजनेस लीडर्स के साथ सीधी बातचीत करेंगे ताकि उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें दूर किया जा सके।

उत्तराखण्ड की सड़क अवसंरचना को 7 हजार करोड़ की मिली सहमति

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य से संबंधित सड़क एवं अवसंरचना विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक एवं रणनीतिक महत्ता, तीर्थाटन, पर्यटन तथा आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में सुदृढ़ एवं आधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य के लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय का अनुरोध किया।

केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के अंतर्गत वर्ष 2026-27 हेतु राज्य सरकार को लगभग रूपये 750 करोड़ लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति पर सहमति प्रदान की गई। इसके साथ ही NHO के अंतर्गत 05 प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग रूपये 2966 करोड़ है। इनमें श्रीनगर बाईपास का च्डब, पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार मार्ग की चार-लेनिंग, लोहाघाट एवं पिथौरागढ़ बाईपास की ंपहदउमदज , मझोला से खटीमा के आबादी भाग में चार-लेन विस्तार तथा रामनगर-रानीखेत (मोहन) मार्ग का सुदृढ़ीकरण प्रमुख रूप से शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 तक की रूपये 530.11 करोड़ की लंबित प्रतिपूर्ति राशि शीघ्र अवमुक्त किए जाने का भी अनुरोध किया।मुख्यमंत्री ने आगामी अधकुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत हरिद्वार बाईपास परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे यातायात दबाव में कमी आएगी तथा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कोटद्वार बाईपास परियोजना के कार्यों में भी तेजी लाने का अनुरोध किया, जिससे क्षेत्रीय यातायात व्यवस्था सुगम हो सके तथा स्थानीय जनता को जाम की समस्या से राहत मिले।दोनों ही प्रस्तावों को सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने छंजपवदंस भ्पहींले पर ैचनत के माध्यम से अन्य मार्गों के संयोजन हेतु कुछ परियोजनाओं के लिए लगभग रूपये 3000 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक सहमति व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा सिकुड़ा बैंड से एनएच-309 तक टनल सहित मोटर मार्ग निर्माण हेतु लगभग रूपये 300 करोड़ की परियोजना पर चर्चा और सैद्धान्तिक सहमति की गई। राज्य में आपदा प्रबन्धन में सफल और कुशल कार्यों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर (ULMMC) के माध्यम से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में उपचारात्मक कार्यों हेतु डीपीआर तैयार किए जाने हेतु डवन करने का अनुरोध किया जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी एवं वैज्ञानिक समाधान सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है।

भारत और मलेशिया ने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की

नई दिल्ली। भारत-मलेशिया सैन्य सहयोग उप-समिति (एससी एमसी) की 12वीं बैठक 1 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अमिताभ प्रसाद और मलेशियाई सशस्त्र बलों के रक्षा संचालन एवं प्रशिक्षण सहायक चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल आमेर महमूद बिन अब्दुल रहमान ने की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की और अब तक हुई निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। चर्चा में चल रही रक्षा गतिविधियों को शामिल किया गया, जिनमें सैन्य आदान-प्रदान, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, स्टाफ वार्ता, क्षमता निर्माण, समुद्री सहयोग और उभरते क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं। दोनों पक्षों ने नियमित द्विपक्षीय गतिविधियों के सफल संचालन को स्वीकार किया और आदान-प्रदान, पेशेवर बातचीत और एक-दूसरे के सैन्य पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण संस्थानों में भागीदारी बढ़ाकर अपनी रक्षा बलों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडलों ने रक्षा उद्योग, रक्षा प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस ढांचे में एक-दूसरे की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ कार्य समूह के तहत व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया।

स्वामी एवं प्रकाशक मौ. वसी के लिये मुद्रक नुसरत निशान खान द्वारा कौमी गुलदस्ता प्रिंटर्स, विलेज आमवाला, पोस्ट घंघौरा, देहरादून द्वारा, उत्तराखण्ड-248141 से मुद्रित एवं 5, लेन नम्बर 2, नामदेव एन्क्लेव फेस 2, ब्राहम्णवाला, देहरादून उत्तराखण्ड- 248171 से प्रकाशित। सम्पादक-मौ. वसी,
समस्त विवाद के लिये न्याय क्षेत्र देहरादून मान्य होगा। सम्पर्क- 9411112331
हमारे अखबार के ताजा अंक को ऑनलाइन पढ़ने के लिये www.aawamindia.com वेबसाइट पर जायें।
facebook: www.facebook.com/indiaaawam, youtube:www.youtube.com/@aawamindia,
X:www.x.com/aawamindia, Instagram:https://instagram.com/aawamindia